दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, रविवार 09 मई 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 218

महत्वपूर्ण एवं खास

जेलों से भीड़ कम करने कैदियों को करें रिहाः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोविड-19 के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को जेलों में भीड़ कम करने का निर्देश देते हुए कहा कि जिन कैदियों को पिछले साल महामारी के मद्देनजर जमानत या पैरोल दी गई थी उन सभी को फिर वह सुविधा दी जाए। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की एक पीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश पर बनाई गई राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की उच्चाधिकार प्राप्त समितियों द्वारा पिछले साल मार्च में जिन कैदियों को जमानत की मंजूरी दी गई थी, उन सभी को समितियों द्वारा पुनर्विचार के बगैर पुनः वह राहत दी जाए, जिससे विलंब से बचा जा सके। कोर्ट की वेबसाइट पर शनिवार को अपलोड हुए आदेश में कहा गया कि इसके अलावा हम निर्देश देते हैं कि जिन कैदियों को हमारे पूर्व के आदेशों पर पैरोल दी गई थी उन्हें भी महामारी पर लगाम लगाने की कोशिश के तहत फिर से 90 दिनों की अवधि के लिये पैरोल दी जाए। एक फैसले का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत ने अधिकारियों से कहा कि उन मामलों में यांत्रिक रूप से गिरफ्तारी से बचें जिनमें अधिकतम सजा सात वर्ष की अवधि की है।

केन्द्र ने राज्यों को अब तक 17 करोड़ 49 लाख से अधिक कोविड टीकों की आपूर्ति की

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारत सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग के साथ सरकार के सर्वांगीण दृष्टिकोण के माध्यम से कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रही है। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और कोविड उचित व्यवहार के साथ, टीकाकरण महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार की पांच सूत्री रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। कोविड-19 टीकाकरण के तीसरे चरण की उदार और त्वरित रणनीति एक मई, 2021 से लागू की गयी है। 28 अप्रैल से नय पात्र जनसंख्या समूहों के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। संभावित लाभार्थी सीधा कोविन पोर्टल पर या आरोग्य सेतु ऐप के जरिए पंजीकरण करा सकते हैं। भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 17.49 करोड़ से ज्यादा टीके की खुराक प्रदान की हैं। अभी भी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास कोविड टीके की 84 लाख से अधिक खुराक(84,08,187) उपलब्ध हैं।

महिला सैन्य पुलिस का पहला बैच भारतीय सेना में शामिल

नईदिल्ली (आरएनएस)। बेंगलुरु स्थित कोर्स ऑफ मिलिट्री पुलिस सेंटर एंड स्कूल (सीएमपी सी एंड एस) ने शनिवार को द्रोणाचार्य परेड ग्राउंड में 83 महिला सैनिकों के पहले जत्थे की अनुप्रमाणन परेड का आयोजन किया । सभी कोविड संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस परेड का आयोजन नियंत्रित ढंग से किया गया था। सीएमपी सेंटर एंड स्कूल के कमांडेंट ने परेड की समीक्षा करते हुए नवप्रमाणित महिला सैनिकों को उनकी त्रुटिहीन ड्रिल के लिए बधाई दी, साथ ही 61 सप्ताह के कड़े प्रशिक्षण- आधारभूत सैन्य प्रशिक्षण, प्रोवोस्ट ट्रेनिंग जिसमें सभी प्रकार की पुलिस संबंधी ड्यूटी एवं युद्धबंदियों का प्रबंधन शामिल है, वाहनों के रखरखाव एवं ड्राइविंग से जुड़ा कौशल विकास एवं सिग्नल संचार शामिल है- के पूरा होने पर शुभकामनाएं प्रेषित की।

देश के सात राज्यों में कोविड मरीजों के लिए 17 रेलवे स्टेशनों पर आइसोलेशन कोच तैनात

नईदिल्ली (आरएनएस)। कोविड-19 के खिलाफ चल रही लड़ाई में, रेलवे के अधिकारियों और टीम ने समय-समय पर और समन्वित कार्रवाई के माध्यम से राज्यों के स्वास्थ्य अधिकारियों और प्रशासन तक पहुंचने के लिए प्रयास जारी रखा है। केंद्रित निगरानी और कार्यों के विस्तृत प्रोटोकॉल के माध्यम से, रेलवे ने राज्यों की मांग के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों में आइसोलेशन कोच पहुंचा दिया है। प्लेटफॉर्म पर तैनात किए गए आइसोलेशन कोचों को विधिवत रूप से बंद कर दिया गया है और उन्हें अलग जगह खड़ा किया गया है और वहां ड्यूटी पर चिकित्सा कर्मियों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जहां पीपीई किट को निकालने और पहने की स्थायी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं, रेलवे ने पुरुषों और महिला स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कोचों में अलग से अस्थायी व्यवस्था प्रदान करने का प्रयास किया है। आरपीएफ स्टाफ को चौबीसों घंटे इन स्वास्थ्य सुविधाओं की देखभाल के लिए तैनात किया गया है। रेलवे ने आपात स्थितियों में प्रत्येक कोच में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर और आग बुझाने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, रेलवे ने इन कोचों में मरीज के आने-जाने के लिए के लिए रास्ते का मार्गदर्शन, रैंप सुविधा भी तैयार की है।

इन आइसोलेशन कोच को देश के 7 राज्यों के 17 स्टेशनों पर तैनात किया गया है और वहां कोविड केयर के मरीजों के लिए खान-पान की व्यवस्था की जाती है। वर्तमान में विभिन्न राज्यों को 4700 बिस्तर वाले 298 कोविड केयर कोच को सौंप दिए गए हैं । 7 राज्यों में कोच की तैनाती इस प्रकार हैः-

इसके तहत रेलवे ने महाराष्ट्र राज्य में 60 कोच तैनात किए हैं। ऐसा देखा गया है कि नंदरबार में कोविड रोगियों का पंजीकरण न केवल बढ़ा है बल्कि आइसोलेशन अवधि के बाद चिकित्सीय सुविधा के बाद तेजी से मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा 116 रोगियों का पंजीकरण किया गया और उसमें से 93 मरीज राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों के जरिए इलाज कराकर स्वस्थ हुए जबकि 23 मरीज अभी इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं। रेलवे ने अजनी इनलैंड डिपो पर मौजूद 11 कोविड केयर कोच (जिसमें से एक कोच में विशेष रूप से चिकित्सा कर्मी और आपूर्ति की व्यवस्था की गई है) को नागपुर नगर निगम को सौंप दिया है। यहां 9 मरीजों को भर्ती किया गया और सभी को आइसोलेट कर दिया गया। पालघर में जहां रेलवे ने हाल ही में 24 कोच प्रदान किए हैं वहां भी अब यह सुविधा शुरू हो गई है।

रेलवे ने मध्य प्रदेश में 42 कोच तैनात किए हैं। पश्चिम रेलवे के रतलाम डिवीजन ने इंदौर के पास तिही स्टेशन पर 320 बेड की क्षमता वाले 22 कोच तैनात किए हैं। यहां अब तक 21 मरीजों को भर्ती किया गया है जबकि 7 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। वहीं भोपाल में 20 कोच तैनात किए गए हैं। इस सुविधा में, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 11 रोगियों के साथ 29 लोगों को भर्ती किया चुका है। आज की तिथि में 18 मरीज इस सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सुविधा में 302 बिस्तर उपलब्ध हैं।

नवीनतम जानकारी के अनुसार असम की ताजा मांग के तहत रेलवे ने गुवाहाटी में 21 आइसोलेशन कोच को पहुंचाया गया है और 20 आइसोलेशन कोच को सिलचर (एन.एफ.रेलवे) के पास बदरपुर ले जाया गया है। इसके पहले इसी सप्ताह में साबरमती, चंदलोदिया और दीमापुर में आइसोलेशन कोच तैनात किए गए थे। दिल्ली में रेलवे ने राज्य सरकार की मांग को पूरा करते हुए 1200 बेड की क्षमता वाले 75 कोविड केयर कोच पहुंचाए हैं। इसके तहत 50 कोच शकूरबस्ती और 25 कोच आनंद विहार स्टेशनों पर तैनात किए गए हैं। 5 मरीजों का पंजीकरण किया गया था और सभी को छुट्टी मिल गई है। यहां कुल 1200 बेड उपलब्ध हैं।

उत्तर प्रदेश में हालांकि कोच की अभी तक राज्य सरकार द्वारा मांग नहीं की गई है। हालांकि फैजाबाद, भदोही, वाराणसी, बरेली और नजीबाबाद में प्रत्येक जगह पर 10 तैयार रखे गए हैं, जिनकी कुल क्षमता 800 बेड (50 कोच) है।

छत्तीसगढ़ एवं मप्र के एनटीपीसी स्टेशनों द्वारा कोरोना महामारी के लड़ाई में अग्रणी भूमिका में

रायपुर (आरएनएस)। विद्युत प्रमुख एनटीपीसी लिमिटेड ने कोविड-19 महामारी की दुसरी लहर के खिलाफ लड़ाई में अपना समर्थन दिया है। पश्चिम क्षेत्र -2 के सभी स्टेशनों और परियोजनाओं ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में समर्थन प्रदान करने के लिए अपने संबंधित जिला प्रशासन के साथ सहयोग किया है ।मार्च 2020 में कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान बिजली क्षेत्र के कर्मियों ने यह सुनिश्चित किए कि बिजली का उत्पादन राष्ट्रीय ग्रिड में सुचारु रहे और घरों में विद्युत उपलब्ध रहें तथा सभी आपातकालीन सेवाएं निर्बाध रहें ।एनटीपीसी सीपत जिला प्रशासन को पीपीई किट और वेंटीलेटर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने से लेकर मस्तूरी में कोविड केयर सेंटर स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

एनटीपीसी कोरबा स्टेशन कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए कोरबा जिला कोविड अस्पताल के लिए सीटी स्कैन मशीन प्रदान करने के लिए आगे आया है। वे आस-पास के गाँवों में नियमित रूप से स्वच्छता का काम भी कर रहे हैं। एनटीपीसी लारा ने भी आगे आकर सार्स-कोव-2 के मद्देनजर वेंटिलेटर खरीदने के लिए कलेक्टर, रायगढ़ को वित्तीय सहायता प्रदान की है। क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक (पश्चिम-2) संजय मदान ने कहा कि ये कठिन समय हैं और हम सभी इसमें एक साथ हैं।

डीआरडीओ की रामबाण दवाई को डीसीजीआई ने दी मंजूरी

» कोरोना को खत्म करने के साथ ऑक्सीजन की कमी भी होगी दूर

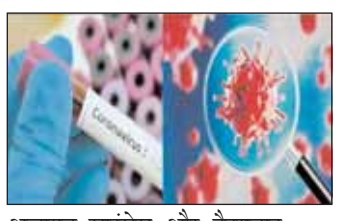

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से मचे हाहाकार के बीच शनिवार को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना के इलाज के लिए एक दवा के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी है। इस दवा का नाम 2- डिऑक्सी-डी-ग्लूकोज नाम दिया गया है। ये दवा डीआरडीओ के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलायड साइंसेस और हैदराबाद सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्युलर बायोलॉजी ने साथ मिलकर बनाया है।

दवा को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस के बढ़ते केस में यह रामबाढ़ साबित हो सकता है। डीसीजीआई के मंजूरी से पहले यह दवा क्लीनिकल ट्रायल्स में सफल साबित हुई है। जिन मरीजों पर इस दवा का ट्रायल किया गया था वो बाकी मरीजों की तुलना में जल्दी रिकवर हुए और इलाज के दौरान ऑक्सीजन पर उनकी निर्भरता भी कम रही। देश में कोरोना वायरस की पहली लहर सामने आने के बाद ही डीआरडीओ इस दवा पर काम करना शुरू कर दिया था। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने अप्रैल 2020 में लैब में इस दवा पर रिसर्च किए थे। रिसर्च में पता चला कि यह दवा कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मददगार साबित हो सकती है। जिसके बाद डीसीजीआई ने मई 2020 में दवा के दूसरे फेज के ट्रायल की मंजूरी दी।डीसीजीआई से दूसरे फेज के ट्रायल की अनुमति मिलने के बाद अलग-अलग हिस्सों में कुल 11 अस्पतालों में ट्रायल किया गया। मई से अक्टूबर तक चलने वाले इस ट्रायल में 110 मरीजों को शामिल किया गया। ट्रायल के दौरान यह बात सामने आई कि जिन मरीजों को यह दवा दी गई वो बाकी मरीजों की तुलना में कोरोना वायरस से जल्दी रिकवर हो गए। आम मरीजों की तुलना में ट्रायल में शामिल मरीज लगभग 2.5 दिन पहले ठीक हो गए।

देशभर में ऑक्सीजन आवंटन के लिए एक्शन में सुप्रीम कोर्ट

» गठित की 12 सदस्यीय टास्क फोर्स

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान विभिन्न अस्पतालों में हो रही ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है।

जस्टिस डी. वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा बनाई गई इस नेशनल टास्क फोर्स का काम पूरे देश में ऑक्सीजन का मूल्यांकन करने, जरूरत देखना और उसका आवंटन करना होगा। टास्क फोर्स में देशभर के नामी-गिरामी अस्पतालों के प्रमुख डॉक्टरों को शामिल किया गया है। कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक दवाओं, मैनपावर और चिकित्सा देखभाल के

मुद्दों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया भी प्रदान करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है, उसमें शामिल 12 सदस्यों के नाम- वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के पूर्व वाइस चांसलर डॉ. भाभातोश बिस्वास, दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल के चेयरपर्सन डॉ. देवेंद्र सिंह राणा, नारायणा हेल्थ केयर के चेयरपर्सन डॉ. देवीशेट्टी, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज (वेल्लोर) के प्रोफेसर डॉ. गगनदीप कांग, डॉ. जेवी पीटर, मेदांता अस्पताल के चेयरपर्सन डॉ. नरेश त्रेहन, फोर्टिस अस्पताल के डॉ. राहुल पंडित, सर गंगाराम अस्पताल के डॉ. सौमित्र रावत, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायलरी साइंस (दिल्ली) के डॉ. शिव कुमार, मुंबई स्थित ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉ. जरीर एफ., केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव और नेशनल टास्क फोर्स के संयोजक जोकि सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर का अधिकारी होगा- हैं।

पिछले कई दिनों से देश के विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। इस वजह से विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट्स से लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पटना, इलाहाबाद, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन संकट को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को फटकार भी लगा चुका है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले दिनों सुनवाई के समय केंद्र को फटकार लगाई थी और दिल्ली को 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई रोजाना देने के लिए कहा था। कोर्ट ने कहा कि केंद्र को 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की यह सप्लाई तब तक जारी रखनी होगी, जब तक कि आदेश की समीक्षा नहीं की जाती है या कोई बदलाव नहीं होता।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए पिछले दिनों कहा था कि आप हमें कड़े फैसले के लिए मजबूर न करें। कोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि कुछ भी छिपाने के लिए नहीं है तो फिर सरकार आगे आकर देश को यह बताना चाहिए कि किस तरह से केंद्र सरकार की ओर से ऑक्सीजन का आवंटन किया जा रहा है।

विदेशों से प्राप्त सहायता सामग्री के आवंटन के लिए व्यवस्थित ढांचा तैयार

नईदिल्ली (आरएनएस)। वैश्विक समुदाय ने भारत के प्रति एकजुटता और सद्भावना का प्रदर्शन करते हुए कोविड-19 महामारी से मुकाबले में भारत की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। भारत सरकार ने दुनिया के विभिन्न देशों से प्राप्त होने वाली सहायता सामग्री के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटन के लिए एक व्यवस्थित ढांचा तैयार किया है। इससे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड उपचार केंद्रों के लिए चिकित्सा संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी और अस्पतालों में भर्ती कोविड मरीजों की बेहतर देखभाल और प्रभावी नैदानिक प्रबंधन सुनिश्चित होगा।

दुनिया के विभिन्न देशों और संगठनों से 27 अप्रैल से भारत सरकार को अंतरराष्ट्रीय सहायता और मदद के तौर पर कोविड-19 के उपचार संबंधी चिकित्सा आपूर्ति और उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। 27 अप्रैल से 7 मई के बीच दुनिया के अलग-अलग देशों से भारत को अब तक कुल 6608 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 3856 ऑक्सीजन सिलेंडर, 14 ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट 4330 वेंटिलेटर/बीआई पीएपी और रेमडिसिविर की लगभग 3 लाख खुराक प्राप्त हो चुकी हैं। विदेशों से प्राप्त हो रही इस राहत सामग्री को देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसका आवंटन और उसकी आपूर्ति एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।

देश में 9.02 लाख ऑक्सीजन और 1.70 लाख मरीज वेंटिलेटर के सहारे

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार के कारण देशभर में कोविड-19 के 1,70,841 मरीज वेंटिलेंटर पर हैं जबकि 9,02,291 मरीज ऑक्सीजन सहायता पर हैं।

यह जानकारी शनिवार को कोरोना महामारी के हालात पर चर्चा के लिए हुई मंत्री समूह की 25वीं बैठक को ऑनलाइन संबोधित करते हुए हर्षवर्धन ने दी और बताया कि कोविड-19 के मामलों में से 1.34 फीसदी आईसीयू में भर्ती हैं, 0.39 फीसदी वेंटिलेटर पर हैं जबकि 3.70 फीसदी मरीज ऑक्सीजन सहायता पर हैं। उन्होंने कहा कि देशभर में कोविड-19 के 4,88,861 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं जबकि 1,70,841 मरीज वेंटिलेंटर पर हैं और 9,02,291 मरीज ऑक्सीजन सहायता पर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बैठक में हिस्सा लिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। पॉल ने अधिकार प्राप्त समूह-1 के कार्यों को लेकर विस्तृत रिपोर्ट पेश की और अस्पताल में भर्ती मरीजों के प्रभावी नैदानिक प्रबंधन के वास्ते अस्पताल के बुनियादी ढांचा विकास के लिए किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया। सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव गिरिधर अरामाने ने तरल मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन, आवंटन एवं आपूर्ति के वर्तमान परिदृश्य से अवगत कराया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अरामाने के हवाले से बताया कि ऑक्सीजन के घरेलू उत्पादन में प्रतिदिन 9400 मीट्रिक टन से अधिक का इजाफा हुआ है। अरामाने ने ऑक्सीजन के आयात, पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना की स्थिति के अलावा टैंकर की उपलब्धता आदि के बारे में भी जानकारी दी।

देश में खौफनाक हुई कोरोना की रफ्तार, पहली बार एक दिन में 4,187 लोगों की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने जिस प्रकार से कहर बरपा रखा है, उसमें पहली बार 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,187 लोगों की मौत हो गई। वहीं चार लाख से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में 4,01,078 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं अब तक देश में ऐसा पहली बार मौका आया जब एक दिन में 4,187 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हुई है। इस दूसरी लहर के कहर में अब गांवों में दस्तक हो रही है। देश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,38,270 पहुंच गई।

बीते 24 घंटे में सामने आए नए मामलों में से 70.77 प्रतिशत 10 राज्यों से सामने आए हैं जिनमें से महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा 54,022 मामले मिले, जिसके बाद कर्नाटक में 48781 और केरल में 38460 नए मरीज मिले। सबसे ज्यादा दैनिक मामलों वाले अन्य सात राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश (27763), तमिलनाडु (26465), दिल्ली (19832), पश्चिम बंगाल (19216), राजस्थान (18231), आंध्र प्रदेश (17188) और हरियाणा (13867) हैं।

कोरोना को मात देने वालों का इजाफा

स्वास्थ्य मंत्रालय के के मुताबिक देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा जारी है। पिछले 24 घंटे में 3,18,609 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। देश में अब तक 1,79,30,960 मरीज कोरोना वायरस को मात देने में कामयाब हुए हैं। रोजाना के आधार पर दर्ज होने वाले नए कोरोना केसों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बेहद कम है। जबकि फिलहाल

एक दर्जन राज्यों में 80 प्रतिशत सक्रीय मरीज

देश में सक्रिय मामले बढ़कर 37,23,446 पहुंच गए हैं, जो कुल मामलों का 17.01 प्रतिशत है जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर घटकर 81.90 प्रतिशत हो गई है। सक्रिय मामलों की संख्या अमेरिका के बाद सबसे अधिक भारत में है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के उपचाराधीन रोगियों में से 80.68 प्रतिशत मामले 12 राज्यों से हैं। एक आधिकारिक आंकड़े में यह जानकारी दी गई। महाराष्ट्र में उपचाराधीन मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा 6.57 लाख है, उसके बाद कर्नाटक में 536661, केरल में 402997, उत्तर प्रदेश में 254118 और राजस्थान में 199147 मरीज हैं। देश में 14 फरवरी, 2021 से लेकर 7 मई, 2021 तक कोरोना के 1,09,68,039 मामले आ चुके हैं, जबकि 30 जनवरी 2020 से लेकर 14 फरवरी 2021 तक इससे कम मामले (1,09,16,481) आए थे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और बिहार में भी उपचाराधीन रोगियों की संख्या ज्यादा है।